संख्या–184/xxxi(13)G-2012-61(सू0अ0)/2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादूनः दिनांकः 08 जून, 2012

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

प्रायः देखा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदक लोक सेवकों की वार्षिक चरित्र–पंजिका की छाया प्रतियॉ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं। विभागों में वार्षिक चरित्र पंजिका के उद्धरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्गत करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है। उक्त के निराकरण के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग का श्री गोपाल कुमार बनामम मेजर जनरल गौतम दत्त व अन्य में द्वितीय निर्णय दिनांक 13.7.2006 उल्लेखनीय हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा

श्री गोपाल कुमार बनाम मेजर जनरल गौतम दत्त व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.7.2006 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर–12 से 16 के उद्धरण नीचे दिये जा रहे हैं :–

"12. The Important point for examination in the request for information related to DPC proceeding and ACRs of the appellant as well as the another person is whether they contain " personal information" and whether they attract the provisions of the official Secrets Act and if so, whether the public interest commends disclosure.

13. In regard to the annual confidential report of any officer, it is our view that what is contained therein is undoubtedly 'personal information' about that employee. The ACRs are protected from disclosure because arguably such disclosure seriously harm interpersonal relationship in a given organization. Further, the ACR notings represent an interaction based on trust and confidence between the officers involved in initiating, reviewing or accepting the ACRs. These officers could be seriously embarrassed and even compromised if their noting are made public. There are, thus reasonable grounds to protect all such information through a proper classification under the Official Secrets Act.

14. No public purpose is going to be served by disclosing this information. On the contrary it may lead to harming public interest in terms of compromising objectivity of assessment – which is the core and the substance of the ACR, which may result from the uneasiness of the Reporting, Reviewing and the Accepting officers from the knowledge that their comments were no longer confidential. These ACRs are used by the public authorities for promotions, placement and grading etc. Of the officers, which are strictly house-keeping and man management functions of any organization. A certain amount of confidentiality insulates these actions from competing pressures and thereby promotes objectivity.

15. We, therefore, are of the view that apart from being personal information, ACRs of officers and employees need not be disclosed because they do not contribute to any public interest. It is also possible that many officers may not like their assessment by their superiors to go into the hands of all and sundry. If the reports are

good, these may attract envy and if these are bad, ridicule and derision. Either way it affects the employee as well as the organization he works for. On balance, therefore, confidentiality of this information serves a larger purpose, which far out-strips the arguments for its disclosure.

16. We are aware that there are forceful arguments for a system of open assessment of employees working for an organization. But, that should be a conscious decision of the organization concerned and must be part of an overall systemic change. Till that happens, confidentiality of annual assessment of the employees of an organization should be allowed to be maintained, if that is the norm in that organization."

2. उपरोक्त से वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों की छायाप्रति आवेदन करने पर उसे निर्गत किये जाने के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक सेवकों की वार्षिक चरित्र पंजिकाओं की छायाप्रति मांगे जाने पर उक्तानुसार आवेदक को वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि की छायाप्रति न देने के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय से अवगत करा दें। उन्हें यह भी निर्देश दे दें कि आवेदक को सूचना प्रकटन न करने के आधार स्वरूप वे केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय उक्त अंश की ओर भी ध्यान आकृष्ट कर दें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्या : /XXXI(13) G-2012-61(सू.अ.)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय।
3. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के अनुरोध सहित प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
उप सचिव।